संपादकीय जागरण
रविवार, 4 मार्च, 2018 : चैत्र कृष्ण 3 वि. 2074

जीवन की रिक्तता ईश्वर की शरण में जाने से ही पूर्ण होती है

भाजपा का विजय रथ

त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के चुनाव नतीजों के साथ केवल भाजपा का विजय रथ और तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ ही नहीं दिख रहा है, बल्कि पूर्वोत्तर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में भी आता नजर आ रहा है। इसके लिए एक बड़ी हद तक श्रेय भाजपा को ही जाता है। उसने राजनीतिक तौर पर अलग-थलग से पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में लाने का काम किया। अगर भाजपा त्रिपुरा में प्रबल जीत के साथ नगालैंड में प्रभावशाली प्रदर्शन करने और मेघालय मे उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही तो यह केवल जोरदार चुनाव प्रचार का नतीजा नहीं है। यह पूर्वोत्तर के राज्यों में विशेष ध्यान देने की उसकी रणनीति का भी परिणाम है। उसने इस रणनीति पर 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही अमल शुरू कर दिया था। असम में चुनाव जीतने के साथ उसने इस रणनीति को और धार दी। राजनीतिक तौर पर सक्रियता दिखाने के साथ ही केंद्र सरकार ने जिस तरह पूर्वोत्तर को अपनी एक्ट ईस्ट एशिया नीति की धुरी बनाया उससे उसने इस इलाके के लोगों को यह भरोसा भी दिलाया कि वह उनके आर्थिक उत्थान के प्रति भी सजग-सचेत है। वाम दलों के मजबूत गढ़ त्रिपुरा में बाजी पलटने जा रही है, यह उसी समय स्पष्ट हो गया था जब मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि उनका मुख्य मुकाबला भाजपा से ही है। इसी तरह नगालैंड की हवा का रुख भी तब साफ हो गया था जब वहां के प्रमुख क्षेत्रीय दल भाजपा से हाथ मिलाने को आतुर थे। निःसंदेह मेघालय में भाजपा उम्मीद से पीछे रह गई, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि यहां भी कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना आसान नहीं।

त्रिपुरा में भाजपा के सत्ता में आने का रास्ता साफ होने के साथ ऐसे राज्यों की संख्या 20 होने जा रही है जहां भाजपा अथवा सहयोगी दलों की सरकारें हैं। भाजपा के मुकाबले राष्ट्रीय हैसियत वाली कांग्रेस तीन-चार राज्यों तक सिमटती दिख रही है तो एक समय राष्ट्रीय राजनीति में असर रखने वाले वाम दल केवल केरल तक सिमट गए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद उन्होंने अपने एक और गढ़ त्रिपुरा को खो दिया। इसके लिए वे अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। चुनाव नतीजे यह बता रहे हैं कि त्रिपुरा के लोग एक विकल्प की तलाश में थे और वह उन्हें कांग्रेस में नहीं उस भाजपा में नजर आया जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती थी। इसी कारण त्रिपुरा में भाजपा की जीत कहीं अधिक प्रभावशाली है। ऐसी चुनावी सफलता के दूसरे उदाहरण मिलना मुश्किल हैं। जहां त्रिपुरा में भाजपा की सफलता अकल्पनीय है वहीं वाम दलों और कांग्रेस की पराजय एक ऐसा आघात है जिसके असर को अन्य विपक्षी दल भी महसूस करेंगे। निःसंदेह भाजपा ने त्रिपुरा और नगालैंड फतह करके आगामी विधानसभा चुनावों के साथ-साथ आम चुनावों के लिए भी वह जरूरी ऊर्जा हासिल कर ली है जो विपक्षी दलों के लिए चुनौती बनेगी, लेकिन अब जब भाजपा का विजय रथ और आगे बढ़ चला है तब उसे लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती पूरी करने पर और ध्यान देना चाहिए।

हद कर दी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी घपलेबाजी शुरू हो गई है। फर्रुखाबाद में पैसे और दान के सामान के लालच में तीन विवाहित जोड़ों के भी फेरे करा दिए गए। जांच में पोल खुलने पर अधिकारियों ने दान का सामान भी वापस मंगा लिया और उनके खातों में भेजी गई अनुदान राशि की रिकवरी कराने की बात कही है। औरैया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नव विवाहिताओं को चांदी की जगह गिलट के जेवर थमा दिए गए। कन्नौज के तिर्वा कस्बे में योजना का लक्ष्य पूरा करने को विवाहित जोड़े भी शामिल करने की हकीकत उजागर हो गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जिस मकसद के साथ प्रारंभ की गई थी, अधिकारी और कर्मचारी गठजोड़ उसमें पलीता लगाने में जरा भी संकोच नहीं कर रहा। आए दिन इस योजना में धांधली की खबरें आ रही हैं। आश्चर्यजनक बात है कि यह सब तब हो रहा है जब योजना की मॉनीटरिंग उच्च स्तर पर की जा रही है। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के पीछे मंतव्य था कि निर्धनों को भी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी और प्रशासन उनकी पेशानी पर तनिक भी बल नहीं पड़ने देगा, लेकिन चिंताजनक बात है कि उम्मीदों के विपरीत यह योजना चलाई जा रही है। भारतीय संस्कृति में कन्या का विवाह महज एक रस्म नहीं बल्कि महती पुण्य कर्म माना गया है। वास्तव में इस पुण्य कर्म के नाम पर उगाही और नकली सामान देकर अपनी जेब भरने वाले तत्व वस्तुतः बड़े अपराधी हैं। यह सराहनीय पहलू है कि उच्च अधिकारियों ने ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर रपट दर्ज कराने में जरा भी देर नहीं लगाई।

> मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जिस मकसद के साथ शुरू की थी, अधिकारी व कर्मचारी उसमें पलीता लगाने में संकोच नहीं कर रहा

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या तीसरी तिमाही में 7.2 फीसद की विकास दर अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार का संकेत है?

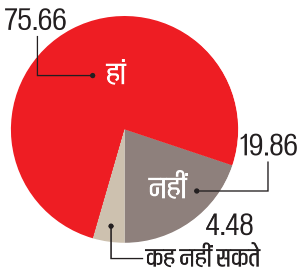

आज का सवाल

क्या त्रिपुरा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, N–नहीं, C–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सिस्टम को और सुधारने का समय

संजय गुप्त

हालांकि सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह ईवे बिल सिस्टम सही से लागू नहीं कर सकी

केंद्र सरकार के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि एक ओर जहां भाजपा ने त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में शानदार प्रदर्शन किया वहीं जीडीपी के ताजा आंकड़ों ने यह बताया कि अर्थव्यवस्था ने फिर तेज रफ्तार पकड़ ली है। राजनीति के साथ आर्थिक मोर्चे पर हासिल की गई सफलता मोदी सरकार के लिए दोहरी खुशी का अवसर है। आर्थिक मोर्चे पर मिली उपलब्धि देश के लिए भी राहतकारी है, क्योंकि विकास दर के नए आंकड़े इस संदेह को दूर कर रहे हैं कि नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक तौर पर विपरीत असर डालने का काम किया। नोटबंदी के बाद एक तिमाही की विकास दर 5.7 प्रतिशत रहने पर कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। अर्थशास्त्रियों के एक समूह की ओर से जीएसटी को भी एक बड़े नकारात्मक असर के रूप में देखा जाने लगा था, लेकिन पिछली दो तिमाही में विकास दर के आंकड़े यह बताते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी के रूप में दो बड़े बदलावों के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। जीडीपी के ताजा आंकड़ों का एक अहम पहलू यह भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। चीन की विकास दर 6.3 प्रतिशत ही आंकी गई। 7.2 प्रतिशत विकास दर के साथ अर्थव्यवस्था के फिर से गति पकड़ने के पीछे जो मुख्य वजह मानी जा रही है वह है बुनियादी क्षेत्रों में विकास की दर तेज होना। ऊर्जा, सीमेंट, विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में हालात सुधरने का असर तेज विकास दर के रूप में सामने आया है। कृषि विकास दर में तेजी आना स्वागतयोग्य तो है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र में वाकई ठोस मजबूती आ गई है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अपने संकल्प को फिर दोहराया। किसानों की आमदनी दोगुनी करना चुनौतीपूर्ण कार्य अवश्य है, लेकिन अगर बुनियादी बदलाव की पहल की जाए तो इस लक्ष्य को हासिल भी किया जा सकता है। किसानों की भांति छोटे व्यापारी और व्यवसायी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जीएसटी के बाद से इस वर्ग को कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। इसका असर कर संग्रह पर भी पड़ रहा है। जनवरी 2018 में जीएसटी संग्रह 86,318 करोड़ रुपये रहा, जो दिसंबर में वसूले गए 86,703 करोड़ रुपये के मुकाबले कम है। अपेक्षा के अनुरूप जीएसटी संग्रह न हो पाना शुभ संकेत नहीं। सरकार को यह देखना होगा कि दो करोड़ टर्नओवर वाले जो व्यापारी जीएसटी में छूट का लाभ ले रहे हैं वे सही-सही कर जमा कराने में कोताही क्यों बरत रहे हैं? चूंकि छोटे और मझोले उद्यम बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करते हैं इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सही से चलें और साथ ही अनावश्यक समस्याओं से दो-चार भी न हों। यह ठीक है कि सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह ईवे बिल सिस्टम समय पर सही से लागू नहीं कर सकी और इसीलिए उसे टालना पड़ा। यह भी ध्यान रहे कि जीएसटी नेटवर्क अभी भी सुगम नहीं हुआ है। कहीं इसी कारण तो कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने में मुश्किल नहीं आ रही है?

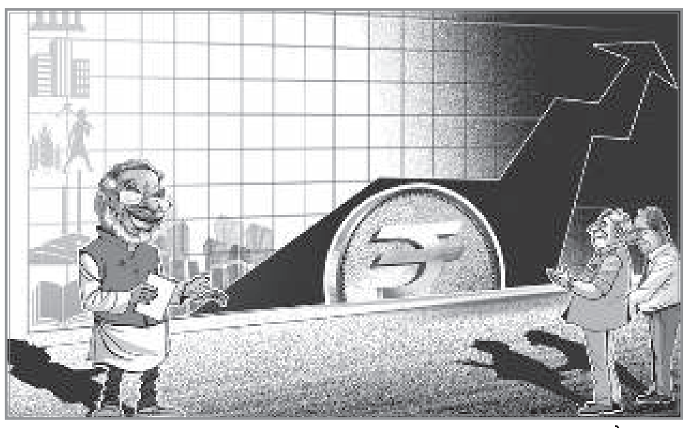

अवधेश राजपूत

यह ठीक है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को लेकर जिस तरह तमाम गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने पीएनबी से कर्ज लेने के क्रम में जिस तरह धोखाधड़ी की उसने बैंकिंग सिस्टम के खोखलेपन को नए सिरे से उजागर किया है। अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक बड़ा आधार बैंकिंग प्रणाली होती है, लेकिन अपने देश में बैंकों के कामकाज में जैसी गड़बड़ियां नजर आ रही हैं और उनकी निगरानी के उपाय जिस तरह नाकाफी साबित हो रहे हैं उससे यह आशंका गहरा रही है कि कहीं यह बैंकिंग सिस्टम अर्थव्यवस्था को ही न ले डूबे। एक अनुमान के अनुसार फंसे हुए कर्जे यानी एनपीए की मौजूदा राशि करीब आठ लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। आशंका यही है कि आने वाले समय में यह राशि और बढ़ सकती है, क्योंकि एक ओर जहां जानबूझकर कर्ज न लौटाने वालों की संख्या बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर बैंक फंसा कर्ज वसूल पाने में असफल साबित हो रहे हैं। बढ़ता एनपीए बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार की ही कहानी कर रहा है। एनपीए बढ़ने न पाए, यह देखना बैंकों का काम है, लेकिन वे सजगता बरतने के बजाय लापरवाही का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए नियामक एवं निगरानी संस्थाओं की सुस्ती भी जिम्मेदार है। एनपीए बढ़ने का बड़ा कारण निजी क्षेत्र के लोगों की ओर से कर्ज लेकर उसे न लौटाने की प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों पर नियंत्रण की रूपरेखा अब जाकर बननी शुरू हुई है। बीते दिनों कैबिनेट ने 'फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर बिल-2018' के मसौदे को मंजूरी दी। इसके कानून का रूप लेने पर भगोड़े आर्थिक अपराधियों की देश-विदेश में स्थित संपत्ति जब्त की जा सकेगी। इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी देने के साथ ही कैबिनेट ने एक स्वतंत्र नियामक संस्था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ऐसी किसी अथॉरिटी की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट घपले-घोटालों को रोक पाने में नाकाम साबित हुए हैं।

घपले-घोटाले करने वालों को दंडित करने में लोकपाल की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, लेकिन अनेक कारणों से लोकपाल के गठन में अनावश्यक देरी हो रही है। लोकपाल बिल में संशोधन का प्रस्ताव दिसंबर 2014 से ही लटका है। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता की जगह सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को मान्यता देने संबंधी संशोधन किया जाना है ताकि वह लोकपाल चयन समिति में हिस्सा ले सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि लोकपाल का चयन नेता विपक्ष के बगैर हो सकता है। इसी के तहत पिछले दिनों लोकपाल चयन समिति की बैठक बुलाई गई और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया गया, लेकिन उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वह चाह रहे हैं कि सरकार पहले लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल यानी कांग्रेस के नेता को नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता दे। पता नहीं क्यों वह यह भूल रहे हैं कि निर्धारित संख्याबल वाले विपक्षी दल के नेता को नेता विपक्ष का दर्जा न देने का कानून कांग्रेस ने ही बनाया था। अच्छा होता कि वह लोकपाल चयन समिति की बैठक में हिस्सा लेते, क्योंकि इससे लोकपाल के गठन की प्रक्रिया को बल मिलता। लोकपाल के गठन के मामले में सरकार को भी सक्रियता दिखानी चाहिए। अभी उसके रुख से ऐसा नहीं लगता कि वह लोकपाल की स्थापना को लेकर प्रतिबद्ध है। लोकपाल समेत अन्य नियामक एवं निगरानी संस्थाओं को मजबूती देना सरकार के एजेंडे में होना चाहिए, क्योंकि मजबूत संस्थाएं न केवल सुशासन में मददगार होती हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक बनती हैं। जब ऐसा होता है तभी सरकार की राजनीतिक सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

response@jagran.com

राष्ट्रीय महत्व वाले चुनाव नतीजे

अवधेश कुमार

त्रिपुरा में भाजपा की जीत और वामदलों की हार से देश से वामपंथ की विदाई की शुरुआत हो सकती है

पांच वर्ष पहले जो भाजपा त्रिपुरा में डेढ़ प्रतिशत मत तक सीमित रही वह वामदलों के मजबूत और एक समय अजेय समझे जाने वाले दुर्ग को इस कदर ढहा देगी, इसकी कल्पना नहीं की जी सकती थी। अगर यह चमत्कार हुआ है तो इसका राजनीतिक असर केवल त्रिपुरा या पूर्वोत्तर राज्यों तक ही सीमित नहीं रह सकता। आखिर जो कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी थी उसका मताधार केवल दो प्रतिशत तक सिमट जाने के कुछ तो राष्ट्रीय निहितार्थ हैं। इस चुनाव परिणाम से माकपा नेतृत्व वाले वाममोर्चे को जबरदस्त धक्का लगा है तो कांग्रेस के लिए यह सन्निपात से कम नहीं है। वाममोर्चा का 25 वर्ष पुराना गढ़ ध्वस्त हुआ तो कांग्रेस त्रिपुरा के साथ नगालैंड में भी साफ हो गई। मेघालय में हालांकि वह सबसे बड़ी पार्टी बनी है, पर बहुमत से दूर है और शेष दलों की सीटें उससे ज्यादा है। नगालैंड के दोनों प्रमुख समूह भाजपा के साथ जाने को तैयार थे, लेकिन भाजपा ने नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ गठबंधन किया। संभव है कि नगा पीपुल्स फ्रंट भी नई सरकार में शामिल हो जाए। तीन राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद भाजपा एवं राजग का विस्तार देश की 68 प्रतिशत आबादी तक हो गया है। यह किसी पार्टी के लिए सामान्य उपलब्धि नहीं है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ उपचुनाव परिणामों से ऐसा लगने लगा था कि शायद देश के मनोविज्ञान में कुछ परिवर्तन आ रहा है, लेकिन तीन राज्यों के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि अभी ऐसे परिवर्तन की कल्पना जल्दबाजी होगी।

सामान्यतः पूर्वोत्तर में असम को छोड़ दें तो अन्य राज्यों के चुनावों की देश स्तर पर हमेशा अनदेखी होती थी। भाजपा को इसका श्रेय देना होगा कि उसने पूर्वोत्तर की राजनीति में देश की अभिरुचि जगाई और उसे देशव्यापी चर्चा में लाई। त्रिपुरा और नगालैंड के जनादेश को केवल पूर्वोत्तर नहीं, बल्कि देश की वर्तमान धारा का परिचायक मानकर चलना होगा। यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल जनादेश की सही तरीके से व्याख्या करें। दुर्भाग्य से वामदलों का आचरण इसके विपरीत दिख रहा है। माकपा ने भाजपा की जीत को धनबल, बाहुबल एवं सांप्रदायिकता की जीत करार दिया। उसने इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ भाजपा के गठबंधन को देशविरोधी तक कहा। यह मानना कि त्रिपुरा के लोगों ने धनबल और बाहुबल के प्रभाव में माकपा का परित्याग कर दिया, जनादेश का अपमान होगा। त्रिपुरा में माणिक सरकार की छवि एक मिलनसार और ईमानदार नेता की रही है, लेकिन उन्होंने विकास के संदर्भ में क्या किया, यह सवाल जनता के सामने था। आखिर भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं वहां किस सुशासन का परिचायक थीं? माकपा और उसके सहयोगी वामदलों को विचार करना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के बाद उनका दूसरा केंद्र इस तरह क्यों ध्वस्त हुआ? बंगाल में हाल में जो उपचुनाव हुए उनमें दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा रही। बंगाल में लगातार पराजय के बावजूद माकपा ने अपने संगठन, विचारधारा और कार्यशैली को लेकर आत्ममंथन नहीं किया। त्रिपुरा में कोई भी देख सकता था कि किस तरह अन्य पार्टियों के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। यह बदलते हुए माहौल का ही परिचायक था। यदि वामदल और कांग्रेस इसे समझने में नाकाम रहे तो यह उनका दोष था। त्रिपुरा में माकपा की पराजय एवं कांग्रेस की सफाई साफ दिख रही थी। त्रिपुरा की जनता विकल्प की तलाश में थी। आखिर वह विकल्प की तलाश में क्यों थी और उन्होंने भाजपा को ही विकल्प के रूप में क्यों चुना? इस पर बाकी दलों को विचार करना चाहिए। त्रिपुरा में भाजपा की विजय और वामदलों की पराजय बड़ी राजनीतिक घटना है। यह देश से वामपंथ की विदाई की शुरुआत हो सकती है। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना तय है। वामदल जितने कमजोर होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी गठबंधन बनने और उसके सशक्त होने की संभावना उतनी ही कम होगी। वामदल केवल केरल तक सिमट गए हैं। उनके अन्यत्र विस्तार की संभावना भी नहीं दिख रही है।

कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। जिस नागालैंड में उसकी तीन बार सरकार रही उसमें वह सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में न रहे और उसके साथ कोई प्रमुख दल गठबंधन को तैयार न हो तो इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? ऐसी कांग्रेस किस तरह 2019 में मोदी और भाजपा को टक्कर दे सकेगी? भविष्य में राजनीति क्या करवट लेगी, इसकी भविष्यवाणी जोखिम भरी होगी, किंतु इस समय यह कल्पना करना कठिन है कि कांग्रेस और वामदल मोदी को कोई सशक्त चुनौती दे पाने की स्थिति में आ जाएंगे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | विमान से हज का किराया

स्रोतः केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

ऊर्जा

प्रेम की भाषाएं

प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता। केवल उदात्त भावनाओं से ही उसे महसूस किया जा सकता है और व्यक्ति को जिससे गहन प्रेम हो जाता है, वह लोगों को नजर भी आने लगता है। प्रेम विस्तृत है, इसकी कोई परिसीमा नहीं है। इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां प्रेम का अंश नहीं है। बस वह उन्हीं लोगों को नजर आता है जो प्रेम को देखने का नजरिया विकसित कर लेते हैं। प्रेम की चार महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। जीवन में यदि व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसे प्रेम की भाषाओं को सीखना ही होगा। किसी भी महान व्यक्तित्व के प्रसिद्ध होने के पीछे प्रमुख कारण यही होता है कि उसे प्रेम की भाषाएं ज्ञात होती हैं और वह उनका समय-समय पर प्रयोग करता है। ये चार भाषाएं हैं-सकारात्मक शब्द, विश्वास, प्रशंसा और मदद की भावना।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं। जो व्यक्ति अपने साथ ही दूसरों के मुश्किल समय में भी सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करता है, वह जीत जाता है और सबका प्रिय भी बन जाता है। प्रेम की दूसरी भाषा है विश्वास। यदि आपका विश्वास गहरा है तो बड़ी से बड़ी चुनौती और कठिनाई भी आपके सामने हार जाएगी। वहीं प्रशंसा का अर्थ केवल तारीफ करना ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर अन्य तत्व भी हैं जैसे कि धन्यवाद देना, लोगों को खास मानकर उनके साथ व्यवहार करना। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है तो वह स्वयं प्रेम के बंधन में बंध जाता है और इस प्रकार प्रेम तत्व चारों ओर बिखर जाता है। प्रेम में सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण है मदद की भावना। जिन लोगों में निस्वार्थ मदद की भावना का संचार होता रहता है वे अपने कर्म और जन्म दोनों को ही सार्थक सिद्ध कर लेते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शब्द, विश्वास, प्रशंसा और मदद की भावना जैसे तत्वों का समावेश रहता है तो उसके अंदर प्रेम की अनुभूतियां स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं और ऐसा व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति को मात देकर विजयी होकर लौटता है। गैरी चैपमैन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द फाइव लव लैंग्वेजेस' में लिखते हैं कि आपके प्रेम का टैंक कभी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रेम का टैंक खाली हो जाता है तो जीवन नीरस और अर्थहीन लगने लगता है।

रेनू सैनी

जवाब देने का वक्त

मौके को ताड़ लेना तो कोई राजनेताओं से सीखे। राजनीति में न कोई छोटा होता है और न बड़ा। इसके लिए समय बड़ी चीज है। केंद्र के एक बड़े मंत्री जी अपने मातहत नायब मंत्रियों को हमेशा अपने काबू में रखते रहे हैं, लेकिन चुनावी साल शुरू होने के साथ ही मातहतों ने उन्हें जवाब देना भी सीख लिया है। पिछले दिनों एक समारोह में महिला नायब मंत्री जोरदार भाषण दे रही थीं। बड़े साहब ने उन्हें अपना भाषण जल्द खत्म करने को लेकर टोकाटोकी शुरू कर दी। फिर क्या था? माननीया बिफरने के अंदाज में पीछे मुड़ीं और बोल पड़ीं, महोदय आप हमसे लंबा भाषण दे दीजिएगा। नायब मंत्री की इस टिप्पणी से बड़े साहब कसमसाए, पर चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समारोह में हिस्सा लेने वालों के बीच इसे लेकर खुसरफुसर शुरू होना लाजिमी था। अब इसके बाद क्या हुआ यह तो मंत्री जी और उनकी नायब ही जानें।

साहब हैं कि मानते नहीं

पढ़ाई-लिखाई से जुड़ा महकमा इन दिनों अपने जूनियर मंत्री के विवादित बोल से परेशान है। यह स्थिति तब है, जब उन्हें सीनियर ने ऐसे विवादों से बचने की साफ हिदायत दे रखी है, लेकिन जूनियर का विवादों से ऐसा गहरा नाता है कि वह थोड़े समय के बाद कुछ ऐसा बोल ही देते हैं कि नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। हाल ही में जूनियर मंत्री ने न्यूटन के गति के सिद्धांत को ही चुनौती दे डाली, वह भी विज्ञान दिवस के मौके पर। उनके इस बोल से वैज्ञानिक आग बबूला हो गए। कड़ी आपत्ति जताई गई है। इससे पहले मंत्री जी ने डार्विन के विकास के सिद्धांत को गलत बताया था। इसके बाद तो विवाद इतना बढ़ा कि सीनियर मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और बुलाकर उन्हें हिदायत दी, लेकिन जूनियर का मिजाज कुछ ऐसा है कि वह कुछ भी मानने तो तैयार नहीं हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती देने वाले मंत्री जी खुद भी विज्ञान के छात्र रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री जी, अब अगली बार किस विवाद को हवा देते हैं।

राजरंग

स्वामी के सताए

भारतीय राजनीति में इस स्वामी के सताये लोगों को संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में जब जांच एजेंसियों ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया तो इसमें भी स्वामी की सक्रियता का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। इनकी सक्रियता का आलम यह है कि सुबह में वह राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े कानूनी मसलों में व्यस्त रहते हैं तो दोपहर में सुनंदा पुष्कर की मौत के राज का पर्दाफाश करने की कोशिश में होते है और शाम को मशहूर बालीवुड अदाकार श्रीदेवी की मौत की 'सच्चाई' को सामने लाने के लिए ट्विटर पर सक्रिय हो जाते हैं। वैसे सत्तापक्ष में भी इनके सताए लोगों की कमी नहीं है। हाल ही में जब कांग्रेस व भाजपा के कुछ नेता आपस में हंसी मजाक कर रहे थे तो एक वरिष्ठ नेता ने कहा, क्यों न 'स्वामी के सताये' लोगों की एक अलग पार्टी बना ली जाए। स्वामी को करीब से जानने वाले तो यह भी कहते है कि निशाना बनाने में स्वामी अपने और पराये का भेद नहीं करते।

बदले-बदले से साहब

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दिल्ली के मुख्य सचिव की पिटाई का मामला जब से सुर्खियों में आया है तब से लुटियंस जोन में बैठने वाले कई अधिकारी दिल्ली सरकार में अपने कार्यकाल की कहानियां सुनाने लगे हैं। कुछ तो बिल्कुल बदले-बदले से नजर आते हैं। हाल में एक वरिष्ठ अधिकारी की केंद्र में तैनाती हुई तो उन्होंने भी अपना अनुभव साझा किया। जो लोग उन्हें जानते हैं उनका कहना है कि जब से यह साहब आप की सरकार में तैनाती के बाद लौटे हैं इनका मिजाज ही बदल गया है। पहले जहां वह सबसे घुलते मिलते और हंसी मजाक करते थे, अब वह बिल्कुल शांत रहते हैं। बहरहाल इसकी वजह तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन यह जरूर कहा कि पहले भी नौकरशाह आप के नेताओं का सितम झेल चुके हैं। अब शायद धीरे-धीरे उनकी दास्तान सामने आए।

ट्वीट-ट्वीट

त्रिपुरा के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में अपना जनादेश भाजपा-आइपीटीएफ सरकार के पक्ष में दिया। हम राज्य के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें 25 साल तक सेवा का अवसर दिया। हम न केवल त्रिपुरा, बल्कि देश में भाजपा और उसके विभाजनकारी एजेंडे का विरोध करते रहेंगे।
सीताराम येचुरी@SitaramYechury

त्रिपुरा से सफाए के साथ वामपंथी विचारधारा अब केवल केरल, जेएनयू, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और चंद न्यूजरूम्स तक सीमित हो गई है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma2

त्रिपुरा में भाजपा का उभार चौंकाने वाला है। टीडीपी, टीआरएस, डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में तेजी के साथ जीरो से हीरो बने, लेकिन एक राष्ट्रीय दल के लिए एक ऐसे राज्य में प्रमुखता से उभरना असाधारण है जहां उसकी कोई उपस्थिति नहीं थी।
रामचंद्र गुहा@Ram_Guha

त्रिपुरा में भाजपा की असाधारण जीत के बीच मैं नगालैंड में भाजपा के शानदार प्रदर्शन को विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा। नगालैंड में भाजपा ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत हासिल की।
राम माधव@rammadhavbjp

जनपथ

बासी गुंझिया खाइए गर्दन तलक दबाय,
खाने से मत चूकिए भले पेट दग जाय।
भले पेट दग जाय मगर मन रहे अधूरा,
हो खाली हर प्लेट बचे ना एकौ चूरा।
होली का क्या लाभ पेट ग़र रहे उदासी,
यदि पड़ोस में जाय न खाई गुंझिया बासी।
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 228